बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 164 ● नई दिल्ली ● शनिवार 28 जून 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

7 रुपये से 3333 आया इस दवा कंपनी के शेयर का भाव, ब्रोकरेज हाउस ने दिया एक और बड़ा टारगेट

नई दिल्ली। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने एक दवा कंपनी के शेयर पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। इसके बाद टॉरेंट फार्मा के शेयरों में 4 फीसदी की तेजी आ गई। ब्रोकरेज फर्म ने इस भारतीय फार्मा कंपनी के शेयर पर ओवरवेट रेटिंग दी है। रिटर्न के लिहाज इस दवा कंपनी के शेयरों ने साल दर साल बेहतर रिटर्न डिलीवर किया है। हालांकि, इस साल अब तक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। वहीं, लंबी अवधि में 46000त से ज्यादा रिटर्न डिलीवर कर चुका है। साल 2001 में टॉरेंट फार्मा के शेयर की कीमत महज 7 रुपये थी। जेपी मॉर्गन ने टॉरेंट फार्मा के शेयरों पर ओवरवेट रेटिंग देते हुए 3,800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है।

मुकेश अंबानी की इस कंपनी के शेयर में आयी जबरदस्त तेजी

नई दिल्ली।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बीएसई पर 5 प्रतिशत तक ऊपर चढ़ गया. बाजार नियामक सेबी की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद मुकेश अंबानी की इस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के शेयर में ऐसी तेजी देखने को मिली है. मार्केट रेगुलेटर की तरफ से जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग को स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग सदस्य बनने की मंजूरी के बाद यह उछाल देखने को मिला है. दरअसल, शुरुआत में इसके शेयर एक दिन पहले बंद भाव 312 रुपये की तुलना में 313.85 पर आकर खुला.

इसके बाद इंट्रा-डे में 5 प्रतिशत की शानदार उछाल के साथ ही ये उछलकर 326.55 रुपये पर आ गया. एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान शुक्रवार को जियो फाइनेंशियल ने बताया कि स्टॉकब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर के तौर पर 25 जून 2025 को जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग प्रा. लि. को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लि. और ब्लैकरॉक इंक के बीच आधे-आधे की साझेदारी है. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया कि 10 जून 2025 को सेबी ने जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया. सेबी से जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को मई के महीने में देश में म्यूचुअल फंड व्यवसाय के लिए निवेश प्रबंधक के तौर पर काम की इजाजत दी गई थी.

इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्क फिलग्रेम का कहना है कि अब वे खुदरा निवेशकों को व्यक्तिगत एडवाइस दे पाएंगे. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने पेमेंट बैंक बांच जियो पेमेंट्स बैंक लि. में करीब 190 करोड़ का इन्वेस्ट किया है.

सोने की चमक पड़ी फीकी, 27 जून 2025 को कितना गिर गया आपके शहर में दाम

नई दिल्ली।

वेस्ट एशिया में शांति के बाद जहां एक तरफ क्रूड ऑयल का भाव तेजी से नीचे गिरा तो वहीं दूसरी तरफ सर्राफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने की चमक फीकी पड़ती हुई दिख रही है. शुक्रवार 27 जून 2025 को सोना के दाम में एक बार फिर से मामूली गिरावट दर्ज हुई है और 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 98,930 रुपये पर कारोबार कर रहा है. एक दिन पहले इसकी कीमत 98,940 रुपये थी. जबकि 22 कैरेट सोना आज 90,680 रुपये और 18 कैरेट सोना 74,190 रुपये के भाव में बिक रहा है. चांदी की कीमत आज 1,07,890 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि एक दिन पहले ये 1,07,900 रुपये के भाव में बिक रही थी. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 98,930 रुपये की दर से बिक रहा है.

जबकि 22 कैरेट सोना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू, चंडीगढ़ और अमरावती में 90,680 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा है. इसी तरह से दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, अमरावती में 18 कैरेट सोना 74,180 रुपये की दर से बिक रहा है तो वहीं मुंबई में में 18 कैरेट सोना 74,730 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा है. जबकि चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और अमरावती में 18 कैरेट सोना 74,180 रुपये के भाव से बिक रहा है. दरअसल, सोने और चांदी का भाव रोजाना के आधार पर तय किया जाता है. अंतरराष्ट्रीय जगत में उथल-पुथल के साथ ही एक्सचेंज रेट, डॉलर की कैल्यू में उतार-चढ़ाव, क्रूड ऑयल जैसे फैक्टर का सोना-चांदी के दाम पर सीधा असर पड़ता है. इसके अलावा, भारतीय समाज में सोने को खास आर्थिक और सामाजिक स्थान प्राप्त है. किसी भी पर्व-त्योहार से लेकर शादी जैसे कार्यों में सोने को बहुत ही शुभ माना जाता है. इसके साथ ही, यहां पर किसी भी परिवार के साथ सोने का होने उस परिवार की संपन्नता का प्रतीक माना जाता है. एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि चाहे कितनी भी महंगाई हो, सोना ने हमेशा ज्यादा रिटर्न देनेवाला खुद को साबित किया है. जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल जैसी स्थिति होती है और निवेशकों के मन में किसी तरह की शंका होता है तो सबसे सुरक्षित निवेश के तौर पर वे सोने में पैसा लगाना ही बेहतर मानते हैं.

ग्राहकों के लिए अलर्ट! खाते में 10,000 नहीं तो लेगा जुर्माना, 1 अगस्त से बदल जाएगा नियम

अगर आपका सेविंग अकाउंट डीबीएस बैंक इंडिया में है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक ने अपने ग्राहकों को 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले नए चार्जिंग नियमों की जानकारी दी है। बैंक के अनुसार, अगर मासिक औसत बैलेंस निर्धारित सीमा से कम रहेगा, तो 6फीसदी तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, यह जुर्माना अधिकतम 500 तक सीमित रहेगा। डीबीएस बैंक इंडिया के मुताबिक सामान्य बचत खाते में ग्राहकों का औसत मासिक बैलेंस 10,000 रुपए होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस इससे कम रहता है, तो आपको जुर्माना देना होगा। डीबीएस बैंक ने अपने ग्राहकों को SMS के जरिए भी यह जानकारी दी है। एसएमएस में लिखा गया है कि 1 अगस्त 2025 से, मासिक औसत बैलेंस कम होने पर लगने वाला चार्ज MAB में कमी की राशि का 6फीसदी होगा। यह अधिकतम 500 रुपए तक होगा। डीबीएस बैंक बचत खाते के लिए MAB 10,000 रुपए ही रहेगा। बैंक ने ग्राहकों को जुर्माने से बचने के लिए आवश्यक MAB बनाए रखने की सलाह दी है। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि 1 अगस्त 2025 से नॉन-मेंटेनेंस चार्ज आपके बचत खाते के प्रकार के आधार पर बदल जाएंगे। अलग-अलग खातों के लिए अलग-अलग चार्ज होंगे। इसकी जानकारी आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगी। 1 मई 2025 से डीबीएस बैंक ने एटीएम से कैश निकालने के नियमों में भी बदलाव किया है। अब मुफ्त लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालने पर आपको ज्यादा फीस देनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि वे मुफ्त लिमिट के बाद एटीएम से पैसे निकालने पर अधिकतम 23 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। डीबीएस बैंक अब नॉन-डीबीएस बैंक एटीएम से मुफ्त लिमिट के बाद पैसे निकालने पर 23 रुपए चार्ज करेगा। हालांकि, डीबीएस बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप डीबीएस बैंक के एटीएम से जितनी बार चाहें उतनी बार बिना किसी फीस के पैसे निकाल सकते हैं।

ये जापानी कंपनी भारत में बंद करेगी फ्रिज और वाशिंग मशीन का कारोबार

नई दिल्ली। जापान की बड़ी कंपनी भारत में अपने दो बड़े प्रोडक्ट वाशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर का कारोबार बंद करने की प्लानिंग कर रही है। इस वित्त वर्ष 2025-26 के तहत कंपनी इसे पूरी तरह से लागू कर देगी। पहले जानते हैं कि इसकी क्या वजह रही? दरअसल जापान की दिग्गज कंपनी पैनासोनिक ने वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक रेफ्रिजरेटर और वाशिंग मशीन का कारोबार बंद करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने ये निर्णय बिक्री में अपने नुकसान के चलते लिया है।

असम में कच्चे तेल के कुएं से 16 दिनों से जारी गैस रिसाव पर पाया गया काबू; मंत्री ने सुनाई राहत भरी खबर

नई दिल्ली। तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने असम के सिवसागर जिले के कुएं नंबर आरडीएस- 147ए के गैस रिसाव को सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी। मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर इससे संबंधित के पोस्ट किया।

मकानों के दाम 11फीसदी बढ़ने से पहली तिमाही में बिक्री 20 फीसदी घटी, एनसीआर में सर्वाधिक 27फीसदी बढ़ी कीमत

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में शीर्ष सात शहरों में मकानों की कीमतें सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़ने से बिक्री में 20 प्रतिशत की गिरावट आई। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक के अनुसार, इस दौरान बिक्री घटकर 96,285 यूनिट रह गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 1.20 लाख यूनिट थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), बेंगलूरु, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में घरों की बिक्री में गिरावट आई है।

ट्रम्प शांति दूत हैं या युद्ध दूत ?

इस साल जनवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रम्प खुद को 'शांति दूत' बताकर सत्ता में लौटे थे लेकिन अब उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच जटिल संघर्ष में अमेरिका को शामिल करने का कदम उठाया है। पद संभालने के बाद से ट्रम्प मध्य पूर्व में शांति लाने में सफल नहीं हो पाए हैं। अब वह एक ऐसे क्षेत्र की अगुआई कर रहे हैं जो और बड़े युद्ध की कगार पर है और इसमें अमेरिका एक सक्रिय भागीदार है। पाकिस्तान के कुछ नेताओं और प्रमुख हस्तियों ने ईरान के तीन परमाणु केंद्रों पर अमेरिका के हमले के बाद सरकार से 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नाम की सिफारिश करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। सरकार ने शुक्रवार को एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए घोषणा की थी कि वह हाल में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान निर्णायक राजनयिक प्रयासों के लिए ट्रम्प के नाम की सिफारिश इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए करेगी। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के हस्ताक्षर वाला अनुशंसा-पत्र नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार समिति को भेजा जा चुका है लेकिन अमेरिका द्वारा ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज परमाणु केन्द्रों पर हमले किए जाने के बाद इस फैसले को लेकर आपत्तियां आने लगी है। ट्रम्प की हाल में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बैठक और दोनों के साथ में भोजन करने से 'पाकिस्तानी शासकों को इतनी खुशी हुई' कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने की सिफारिश कर दी। 'चूंकि ट्रम्प अब संभावित शांति दूत नहीं रह गए हैं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जानबूझकर एक अवैध युद्ध छेड़ दिया है, इसलिए पाकिस्तान सरकार को अब नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश पर पुनर्विचार करना चाहिए, उसे रद्द करना चाहिए।' ट्रम्प ने दावा किया है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई, वहीं भारत ने आधिकारिक रूप से इस बात को खारिज कर दिया। भारत सरकार का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी महत्वपूर्ण शांति प्रयास भारतीय कूटनीति और अन्तर्राष्ट्रीय दबावों के कारण हुए थे, न कि यह ट्रम्प की पहल से हुए। वहीं पाकिस्तान ने तो ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार देने का प्रस्ताव तक रख दिया जो एक राजनीतिक मजाक जैसा प्रतीत होता है क्योंकि ट्रम्प की भूमिका को लेकर कोई ठोस तथ्य मौजूद नहीं थे। यदि राष्ट्रपति ट्रम्प वाकई 'शांति दूत' हैं तो फलस्तीन के गाजा में हमले अब भी जारी क्यों हैं? वह रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त क्यों नहीं करवा पाए? यह तो ट्रम्प का मुख्य चुनावी मुद्दा था। इराक, सीरिया, लीबिया, लेबनान, यमन, अफगानिस्तान आदि देशों में अमरीका की युद्धबाज के तौर पर और खुद राष्ट्रपति ट्रम्प की क्या भूमिका रही है? मौजूदा इजराइल-ईरान युद्ध को ही लें। बीते 10 दिन से भीषण हमले जारी हैं। करीब 700 मौतें हो चुकी हैं। ईरान के 12 से अधिक सैन्य जनरल मार दिए गए हैं। परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। कितनी इमारतें और प्रतिष्ठान खंडहर कर दिए गए हैं, उनका डाटा अभी उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रपति ट्रम्प कहते हैं कि वह इजराइल को युद्ध छोड़ने को नहीं कहेंगे। यह कौनसा शांतिकर्म है? ट्रम्प बार-बार बयान बदल रहे हैं। अमरीका युद्ध में शामिल भी है और राष्ट्रपति ट्रम्प ने दो सप्ताह के बाद कोई फैसला लेने की बात कही है। वह दावा करते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जबकि उनकी सरकार में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2003 में ही बंद करा दिया गया था, लिहाजा ईरान परमाणु बम कैसे बना सकता है? ट्रम्प ने उनके बयान को खारिज कर दिया, तो तुलसी को भी सफाई देनी पड़ी। यदि ट्रम्प वाकई 'शांति दूत' हैं तो उनका परमाणु बम से क्या लेना-देना? उनके प्रयास होने चाहिए कि युद्ध अविलंब खत्म हो लेकिन अमरीका की नीयत के मद्देनजर रूस और चीन को चेतावनी देनी पड़ रही है कि अमरीका युद्ध में घुसने की कोशिश न करे। ट्रम्प ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल के पक्ष में कई फैसले लिए, जिसमें यरूशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देना और फिलिस्तीनियों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लागू करना शामिल था। इससे मध्य पूर्व में और तनाव बढ़ा। जबकि मानवता कहती है कि उन्हें फिलिस्तीनी निर्दोषों के नरसंहार पर बोलना था, वे निष्पक्ष नहीं रहे और फिलिस्तीन को धमकाते रहे। 2011 में लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप किया गया जिससे वहां की सरकार गिर गई और देश अस्थिर हो गया। यह कार्रवाई भी उनकी शांति की नीति के खिलाफ मानी जा सकती है। ट्रम्प के शासन में कई देशों के साथ संघर्ष हुए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण ये हैं ट्रम्प ने चीन के खिलाफ ट्रेड वार शुरू किया जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा। उन्हीं ने कई देशों, विशेषकर यूरोपीय देशों, जापान और कनाडा पर उच्च टैरिफ्स लगाए। इस नीति से वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ी। राष्ट्रपति ट्रम्प का नोबेल पुरस्कार के लिए दर्द बार-बार बयां हो रहा है कि वह कितना, कुछ भी कर लें लेकिन उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। उनकी यह छटपटाहट इसलिए भी घनीभूत होती है, क्योंकि 2009 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। डोनाल्ड ट्रम्प की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा पर दुनियाभर के राजनयिक हलकों और मानवाधिकार संगठनों में मिश्रित लेकिन अधिकतर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों के विश्लेषकों का मानना है कि ट्रम्प का ट्रैक रिकॉर्ड संघर्ष और टकराव से भरा हुआ है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने ट्रम्प की नोबेल चाहत को अन्तर्राष्ट्रीय शांति के साथ मजाक कहा है। भारत में सोशल मीडिया पर भी इस पर मीम्स और तंज की बाढ़ आ गई है, जहां यूजर्स ने ट्रम्प के भारत-पाक शांति दावों को 'राजनीतिक नौटंकी' करार दिया।

संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़ कर कांग्रेस ने जो गलती की थी, संसद को उसे सुधारना चाहिए

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया तो कांग्रेस आग बबूला हो गयी। कांग्रेस शायद भूल गयी है कि आपातकाल के दौरान जब सारा विपक्ष जेल में ठूंस दिया गया था तब इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में जबरन दो शब्द जोड़ दिये थे। कांग्रेस को समझना चाहिए कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जब बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे गये संविधान की प्रस्तावना में थे ही नहीं तो उस पर सवाल उठेंगे ही। ऐसा भी नहीं है कि आरएसएस ने ही पहली बार इन दोनों शब्दों पर सवाल उठाया हो। समाज के कई वर्गों की ओर से इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। आरएसएस पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रही कांग्रेस शायद भूल रही है कि उसकी सरकारों ने ही सर्वाधिक बार संविधान में संशोधन किये और संविधान की प्रस्तावना तक को संशोधित कर डाला। इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द तब जोड़े थे जब देश में आपातकाल लगा था और विपक्ष के सारे नेता जेल में थे। यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान में संशोधन किया जा सकता है और यह शक्ति संसद के पास है जो प्रस्तावना तक भी विस्तारित है। मगर उस समय संसद ने लोकतंत्र की भावना के अनुरूप काम नहीं किया और विपक्ष की गैर-मौजूदगी में संशोधन के जरिये प्रस्तावना में भारत के वर्णन को "संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य" से बदलकर "संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" कर दिया गया। उस समय राजनीतिक कारणों से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला गया। कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था, तब 1976 में उसे बदल क्यों दिया गया? कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि 1976 में किये गये संशोधन के बाद भी संविधान की प्रस्तावना में क्यों लिखा है कि उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया? आरएसएस पर सवाल उठा रही कांग्रेस को यह भी पता होना चाहिए कि साल 2023 में नये संसद भवन में कामकाज के पहले दिन सांसदों को दी गई संविधान की प्रति में प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द नहीं थे। उस समय केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि यह मुद्रित प्रति ही मूल प्रस्तावना थी। कांग्रेस को समझना होगा कि संविधान में सामान्य संशोधनों और प्रस्तावना में किये गये संशोधन में बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान अलोकतांत्रिक रूप से जो कार्य किया था अब उसे ठीक करने का आह्वान किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द रहें या नहीं रहें, यदि इस पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद फैसला करने की मांग की जा रही है तो इसमें गलत क्या है?

सम्पादकीय...

आजादी की लड़ाई लड़ते हुए भारत के नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने का आश्वासन दिया था

स्वतन्त्र भारत के इतिहास में 21 महीने का इमरजेंसी काल ऐसा कलंक है जिसकी याद समय-समय पर करके हम अपने लोकतन्त्र को मजबूत बनाये रख सकते हैं। यह समय 25 जून, 1975 से लेकर मार्च 1977 तक का था जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने अपनी गद्दी बचाये रखने के लिए पूरे देश पर आन्तरिक इमरजेंसी लागू कर दी थी और नागरिकों के मौलिक या मूलभूत अधिकारों को समाप्त कर दिया था। उस समय पूरे देश पर ऐसा काला घना अंधेरा छाया था जिसका कोई दूसरा उदाहरण भारत के इतिहास में नहीं था। यह इमरजेंसी समय कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर भी कलंक के समान था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही आजादी की लड़ाई लड़ते हुए भारत के नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने का आश्वासन दिया था। इस दौरान देश के सभी संवैधानिक संस्थानों को अधिकार विहीन व दन्त विहीन कर दिया गया और यहां तक कि स्वतन्त्र न्यायपालिका के अधिकार भी छीन लिये गये। इस दौरान न कोई दलील थी और न कोई अपील थी और न कोई वकील था। पूरे देश को जेलखाने में तब्दील कर दिया था। सभी विपक्षी राजनेताओं व कार्यकर्ताओं तक को जेलों में ठूंस दिया गया था। इनमें मजदूर नेता तक शामिल थे। किसी भी नागरिक के पास अपनी जायज मांग उठाने का कोई जरिया नहीं था और आवाज उठाने पर उसे जेल में डाल दिया जाता था। आजाद भारत ऐसा नजारा पहली बार देख रहा था। अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। पत्रकारों की आजादी पूरी तरह छीन ली गई थी। अखबारों में वही छपता था जिस पर सरकार की सहमति होती थी। यह सब केवल एक व्यक्ति श्रीमती इन्दिरा गांधी की सत्ता को कायम रखने के लिए किया गया था क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून, 1975 को उनका रायबरेली सीट से लड़ा गया लोकसभा चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद इन्दिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए 40 दिन का समय दिया गया था। मगर इस दौरान वह लोकसभा या संसद में किसी मतदान में भाग नहीं ले सकती थीं। इसकी वजह यह थी कि उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इन्दिरा गांधी के पास उस समय कई विकल्प थे। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पास भारी बहुमत था। वह कांग्रेस के ही किसी अन्य नेता को प्रधानमन्त्री बना सकती थी। इसमें सबसे ऊपर नाम उस समय दलित नेता बाबू जगजीवनराम का चल रहा था क्योंकि वह सबसे वरिष्ठ नेता थे और नेहरू काल से ही मन्त्रिमंडल में शामिल थे। परन्तु इन्दिरा गांधी ने यह उचित नहीं समझा और इमरजेंसी लगाने का ठीकरा जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन पर फोड़ते हुए देश में तानाशाही लागू कर दी। इसके लिए संविधान का प्रावधान ढूंढने में तत्कालीन कांग्रेस नेता स्व. सिद्धार्थ शंकर राय ने बहुत मेहनत की, जिसे इन्दिरा जी के छोटे बेटे स्व. संजय गांधी ने पूरा समर्थन दिया। इस प्रकार पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई और सभी आन्दोलनकारी नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। अब आज की मोदी सरकार यदि इस दिन की याद को ताजा रखने के लिए पूरे साल भर कार्यक्रम आयोजित करना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ऐसा करने से देशवासी लोकतान्त्रिक अधिकारों के प्रति सजग होंगे और लोकतन्त्र बचाये रखने का जज्बा उनमें जागृत रहेगा। परन्तु कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पर ऐतराज है। उनका कहना है कि ऐसा करके मोदी सरकार अपनी पिछले 11 साल की विफलताओं को छिपाना चाहती है और आम लोगों को गफलत में रखना चाहती है। श्री खड़गे का तर्क है कि यदि इमरजेंसी लगाने का फैसला इन्दिरा गांधी ने लिया था तो इसे 21 महीने बाद हटाने और निष्पक्ष व स्वतन्त्र चुनाव कराने का फैसला भी उन्होंने लिया था। ये चुनाव 1977 की पहली तिमाही में हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह परास्त हो गई थी और पूरे उत्तर भारत में उसका सफाया हो गया था। केवल दक्षिण भारत के चार राज्यों व अन्य छिटपुट सीटों से कांग्रेस को सफलता मिली थी और इसकी 153 सीटें आयी थीं। यहां तक कि रायबरेली से ही इन्दिरा गांधी अपना चुनाव तक हार गई थीं और उनके पुत्र संजय गांधी भी चुनाव में परास्त रहे थे। श्री खड़गे का तर्क है कि 1977 में जब केन्द्र में कांग्रेस को हराकर जनता पार्टी की सरकार बनी तो वह अधिक समय तक नहीं चल सकी और 1980 में पुनः लोकसभा चुनाव हुए जिसमें इन्दिरा गांधी पुनः भारी बहुमत से विजयी हुई और कांग्रेस पार्टी को दो तिहाई बहुमत से कुछ ही कम सीटें मिलीं। इसका मतलब उनकी नजर में यह निकलता है कि इमरजेंसी की गलती के लिए भारत के लोगों ने इन्दिरा गांधी को केवल तीन साल बाद ही माफ कर दिया था और उनके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया था। बेशक श्री खड़गे के तर्क को लोकतन्त्र में हार-जीत की तराजू पर रखकर देखा जा सकता है मगर इमरजेंसी को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। इमरजेंसी भारत के इतिहास का एक काला अध्याय ही रहेगा जिसे किसी भी तर्क से सफेद नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि लोकतन्त्र में आम जनता ही इस व्यवस्था की सजग प्रहरी होती है अतः यदि मोदी सरकार जनता को इस ओर सजग बनाये रखना चाहती है तो इसका विरोध किस प्रकार किया जा सकता है।

मध्य पूर्व : युद्ध या शान्ति

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि ईरान और इजराइल में युद्ध विराम हो गया है, पर अभी तो दोनों देश एक-दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। मध्य पूर्व का इतिहास बताता है कि यहां शान्ति वार्ता नाजुक रहती है। युद्ध शुरू करना आसान है, खत्म करना मुश्किल। ईरान ने कतर में अमेरिका के सैनिक अड्डे पर 12 मिसाइलें दागी थीं, पर अमेरिका को पहले बता दिया गया था। यह संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ पक चुका है। अगर यह सही है तो ट्रम्प अपने से पहले कई अमेरिकी राष्ट्रपति के भाग्य से बच गए लगते हैं। अभी तक मध्य पूर्व कई अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा का कब्रिस्तान रहा है। पर यह मालूम नहीं कि इजराइल के शैतान प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब शरारत से बाज आएंगे या नहीं ? ट्रम्प ने भी कहा है कि वह नेतन्याहू से 'बहुत 'अप्रसन्न' हैं। इजराइली पत्रकार एंटिला सोमफलवी ने भी सवाल किया है कि «क्या ट्रम्प नेतन्याहू को सीधा कर सकेंगे?» वह आगे टिप्पणी करते हैं कि «युद्ध विराम कायम रहता है या नहीं और पश्चिमी एशिया कम फंसादी बनता है या नहीं, यह अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यता पर निर्भर करता है कि वह नेतन्याहू को युद्ध को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं या नहीं?» मध्य पूर्व में शान्ति अब एक व्यक्ति की राजनीतिक जरूरत पर निर्भर करती है। ट्रम्प तभी नेतन्याहू से नाराज हैं, पर आशा है कि उन्होंने सबक सीख लिया होगा कि ईरान के साथ पंगा लेना आसान नहीं। ईरान कोई मामूली देश नहीं है। पुरानी सभ्यता है। ईरान को भी समझ आ गई होगी कि संकट के समय कोई देश उनके साथ नहीं था। न रूस आया, न चीन और उनका परमाणु ठिकाना ध्वस्त हो गया है। वह शायद अपना परमाणु मैटीरियल बचाने में सफल रहे हैं, पर पूरे परमाणु कार्यक्रम को बहुत धक्का पहुंचा है जिसको फिर से खड़ा करना आसान नहीं होगा। अयातुल्ला खामेनेई के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होंगे कि आखिर में युद्ध विराम मानने पर मजबूर हो गए। उनकी पकड़ कमजोर होगी। ट्रम्प ने ईरान और इजराइल के नेतृत्व की «सहनशक्ति,साहस और बुद्धिमत्ता' की तारीफ की है, पर अगर युद्ध विराम टिक जाता है तो यह ट्रम्प के नेतृत्व की कामयाबी है। यह अमेरिका की कठोर शक्ति का नया प्रदर्शन भी है। कोई देश अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता। अमेरिका बता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वह है जो अमेरिका कहता है। वह किसी भी देश में घुसकर बमबारी कर सकते हैं कोई पूछने वाला नहीं। वह अपने बी-2 विमान भेज कर कहीं भी अपने 30,000 पौंड के बंकर बस्टर बम 300 फुट की गहराई तक मार कर सकते हैं। अमेरिका इत्मिनान से किसी भी देश की प्रभुसत्ता का उल्लंघन कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं कर सकता। अमेरिका की एकतरफा कार्रवाई का निहितार्थ सब समझ गए होंगे। यह आज और भी चिन्ताजनक है क्योंकि वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में वह शख्स रह रहे हैं जिन पर कोई नियम नहीं लगता। डोनाल्ड ट्रम्प को कोई पूछने वाला नहीं है। पश्चिम के देशों की यह पुरानी परम्परा है कि वह विवाद घड़ लेते हैं और बाद में उसका औचित्य निकालते हैं, लेकिन अब अगर युद्ध वास्तव में रुक जाता है तो दुनिया चैन की सांस लेगी। मध्य पूर्व में अगर आग लग जाती तो बहुत तबाही होती। पहले ही दुनिया दो युद्ध, गाजा में और यूक्रेन के युद्ध से निपट रही है। तीसरा युद्ध वह बर्दाश्त नहीं कर सकती और यह युद्ध पहले दो युद्धों से कहीं अधिक खतरनाक साबित हो सकता था क्योंकि ईरान गाजा नहीं है जिसे इजराइल मटियामेट कर सके। यह क्षेत्र बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। केवल ईरान के पास दुनिया के तेल का 10 प्रतिशत और गैस का 15 प्रतिशत है। सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन जैसे देश बड़े तेल उत्पादक देश हैं। ईरान के पास से होर्मुज का जल गलियारा निकलता है जहां से 20 लाख बैरल तेल रोजाना गुजरता है। ईरान या उसके हूती जैसे संगठन इसे बाधित कर सकते थे। इससे दुनियाभर में तेल की कीमतें बढ़ जाती और भारत जैसे देश बुरे प्रभावित होते। डोनाल्ड ट्रम्प की शुरूआत शान्ति कायम करने वाले नेता के रूप में हुई थी, पर इन्हीं डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों, फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी करवा दी। फोर्दो पर हमला महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान की एक पहाड़ी में 295 की गहराई पर ईरान का एनरिचमेंट प्लांट है। इजराइल ने इसे तबाह करने कोशिश की थी, पर इतनी अंदर तक मार करने की क्षमता केवल अमेरिका के पास ही है। ट्रम्प का दावा है कि ईरान के इन तीनों संस्थानों को मिटा दिया गया है। ईरान पर यह हमला क्यों किया गया? नेतन्याहू का कहना है किस मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है। वह नाटकीय भाषा में कहते हैं कि, «दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार रखने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया»। पर क्या ईरान के पास बम है?1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। तीन दशक के बाद वह वही बात दोहरा रहे हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने उनकी संसद के सामने गवाही दी है कि ईरान बम नहीं बना रहा। इस पर ट्रम्प उनसे खफा हो गए थे और तुलसी गबार्ड ने संशोधित करते हुए कहा है कि «ईरान कुछ सप्ताह में» परमाणु हथियार बना सकता है। अर्थात अभी भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख यह मानने को तैयार नहीं कि ईरान के पास बम है। फिर हमला क्यों किया गया? इसका जवाब नेतन्याहू देते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इजराइल के अस्तित्व को खतरा है। पर गाजा के पास तो परमाणु हथियारें नहीं थे फिर वहां इतनी तबाही क्यों की गई कि लोग पानी तक के लिए तरस रहे हैं। बच्चे भूखे मर रहे हैं ? राहत सामग्री के अंदर आने पर बार-बार रुकावटें खड़ी की जाती हैं। हमास ने 7 अक्तूबर 2023 को हमला कर 1200 इजराइली नागरिक मार दिए थे। दुनियाभर में इस घटना की निंदा हुई थी। पर बदला लेने के लिए, तब से लेकर अब तक इजराइल वहां बम बरसा रहा है। 55000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। स्कूलों, अस्पतालों पर बमों से हमले हो चुके हैं। इन लोगों की अंतरात्मा नहीं है? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है?जब सद्दाम हुसैन को खत्म किया गया तब कहा गया कि इराक के पास 'सामूहिक विनाश के हथियार हैं'। जब आखिर में बंकर में छिपे भयभीत सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया तब तक युद्ध के आठ वर्ष बीत चुके थे। हजारों मारे गए और हजारों घायल हुए। पर अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बुश को मानना पड़ा कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार नहीं हैं। अर्थात सारा युद्ध ही फिजूल लड़ा गया। क्या इस बार भी काल्पनिक खतरे को लेकर तबाही मचाई जा रही है? नेतन्याहू तो युद्धोन्मादी है, पर उन्होंने भी देख लिया होगा कि अगर तेहरान तबाह हो रहा था तो तेलअवीव भी बचा नहीं था। तेल अवीव से पत्रकार बता रहे थे कि ईरान की मिसाइलों के सामने इजराइल का आयरन डोम फेल हो रहा था। दुनिया का दुर्भाग्य है कि नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए वह कोई न को संकट खड़ा रखते हैं। वह समस्या हैं समाधान नहीं। वह ईरान में सत्ता पलटने की भी मांग कर रहे हैं। 86 वर्षीय अयातुल्ला खामेनेई 1989 में ईरान के राजनीतिक और आध्यात्मिक सुप्रीम लीडर बन गए थे। तब से लेकर अब तक वह वहां एक कट्टर और सख्त धार्मिक शासन चला रहे हैं। पश्चिम के देश इन्हें हटाना चाहते हैं, पर यह मामला तो ईरान के लोगों का है। नेतन्याहू का यह कहना कि 'खामेनेई का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए' तो असभ्यता की पराकाष्ठा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान के नेता की हत्या की मांग कर रहे हैं। हमारे बहुत हित इस क्षेत्र से जुड़े हैं।

ईरान पुराना मित्र है। चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल हम अफगानिस्तान और केन्द्रीय एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए करना चाहते हैं। पश्चिम एशिया में हमारे लगभग 80 लाख लोग रहते हैं जो वार्षिक 30 अरब डॉलर घर भेजते हैं। हम नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में अस्थिरता आए। दूसरी तरफ इजराइल एकमात्र वह देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी मदद की है। इसलिए हमने किसी की भी आलोचना नहीं की और अगर युद्ध विराम हो जाता है तो भारत चैन की सांस लेगा। ईरान की कमजोरी है कि कोई भी बड़ा देश उसके साथ उस तरह नहीं खड़ा जैसे अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। पुतिन का कहना है कि वह युद्ध से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि इजराइल में 20 लाख रूसी मूल के लोग रहते हैं। चीन तो वैसे ही ऐसे झंझटों से दूर रहता है। उसका ध्यान अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने पर है, जबकि अमेरिका को कोई न कोई देश चाहिए जिसे वह खलनायक करार कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके, पर अगर अब शान्ति हो जाती है और ट्रम्प अपने से पहले राष्ट्रपतियों के 'विदेशी मूर्खतापूर्ण युद्धों' से बच जाते हैं तो उनकी प्रशंसा जरूर की जानी चाहिए। वह एक बच्चे की तरह जो आईसक्रीम के लिए जिद करता है नोबेल सम्मान प्राप्त करने की रट लगा रहे हैं, अगर युद्ध विराम स्थाई रहता है तो हो सकता है कि नोबेल समिति अब देने को तैयार हो जाए।

छात्रों को अंकों में बेहतर सुधार का मौका

वैश्विक स्तरपर भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर पूरी दुनिया के मंझे हुएशिक्षाविदों बुद्धिजीवियों व शिक्षा के क्षेत्र में विशेष विश्लेषणात्मक भूमिका रखने वालों की पूरी नजर गड़ी हुई है, क्योंकि इस नई राष्ट्रीय नीति 2020 में अनेकों ऐसे अनुशंसित नियम व मौके हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत की पीढ़ियों में मील का पत्थर साबित होंगे। इसके पूर्व हमने देखे कि इंजीनियरिंग सहित अनेकों कोर्स अपनी मातृभाषा में करने का सटीक सिस्टम लागू किया गया है, जो इस एनईपी 2020 का ही हिस्सा है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के सभी राज्यों ने भी तुरंत लागू करना चाहिए क्योंकि इस शिक्षा नीति को अपनाने से जोजनरेशन निकलेगी वह पारिस्थितिकोजन्य विश्लेषण कर नई प्रौद्योगिकी वह नीति से आगे बढ़ाने वाली होगी।आज इस विषय पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीबीएसई के एग्जामिनर कंट्रोलर ने बुधवार दिनांक 25 जून 2025 शाम को प्रेस में बताया कि दसवीं की परीक्षा अब सत्र 2025-2026 से वर्ष में दो बार होगी, व उसका पूरा विवरण बताए जो हम नीचे पैराग्राफ में चर्चा करेंगे।चूंकि इस नए पैटर्न से छात्रों को अंकों में बेहतर सुधार करने का मौका मिलेगा जो उनके करियर में मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे सीबीएसई 10वीं बोर्ड का नया पैटर्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुरूप परीक्षाओं को कम तनावपूर्ण व छात्रों को सीखने का बेहतर मौका देना है। साथियों बात अगर हम सत्र 2025-26 से सीबीएसई 10वीं की परीक्षा पैटर्न में चेंज की करें तो,अगर हम या हमारे बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर हमारे लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के तरीके में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है, अब छात्रों को परीक्षा में साल में दो बार बैठने का मौका मिलेगा, यानी अगर कोई छात्र अपने पहले प्रयास के अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह दूसरी परीक्षा में बैठ सकता है, इसका उद्देश्य छात्रों पर से दबाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का दूसरा मौका देना है।सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक ने दी जानकारी दी उन्होंने कहा, "पहला चरण फरवरी में और दूसरा मई में आयोजित किया जाएगा, दोनों चरणों के परिणाम क्रमशः अप्रैल और जून में घोषित किए जाएंगे इससे छात्रों को एक ही शैक्षणिक सत्र में दो अवसर मिलेंगे और वे समय पर अपने करियर और आगे की पढ़ाई के लिए निर्णय ले सकेंगे।उन्होंने आगे कहा, "छात्रों के लिए पहले चरण में शामिल होना अनिवार्य होगा, जबकि दूसरा चरण वैकल्पिक होगा, छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का मौका मिल सकेगा, इसका मतलब यह है कि छात्र केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दोबारा देंगे, जिनमें वे अपनी पहली कोशिश से संतुष्ट नहीं हैं तय मानदंडों के अनुसार, शीतकाल में बंद रहने वाले स्कूलों के दसवीं कक्षा के छात्रों को किसी भी चरण में उपस्थित होने का विकल्प मिलेगा, इसके अनुसार, शैक्षणिक सत्र के दौरान आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा, यह बदलाव परीक्षा प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है, सीबीएसई ने फरवरी में मसौदा मानदंडों की घोषणा की थी और हितधारकों की प्रतिक्रिया मांगी गई थी, नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के मुताबिक, बोर्ड परीक्षाओं की "उच्च अपेक्षा वाले पहलू को खत्म करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी शैक्षणिक वर्ष के दौरान दो मौकों पर परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।सीबीएसई का यह नया पैटर्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। नीति का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं को कम तनावपूर्ण बनाना और छात्रों को सीखने के बेहतर मौके देना है,सीबीएसई ने इस बदलाव से पहले फरवरी 2025 में ड्राफ्ट नियम जारी कर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे थे,इन सुझावों के आधार पर ही यह नया पैटर्न तैयार किया गया है। सीबीएसई का यह नया फैसला बोर्ड परीक्षा को ज्यादा लचीला और छात्र- केंद्रित बनाता है, अब छात्र अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दो मौके पा सकेंगे, जिससे परीक्षा का तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कक्षा 10 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा के पहले चरण में उपस्थित होना अनिवार्य, दूसरा चरण वैकल्पिक रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा।इस फैसले के बाद छात्रों को अपने अंकों में सुधार का मौका मिल पाएगा। यदि किसी छात्र के अंक पहले चरण में कम रह जाते हैं, तो वह दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन करके सुधार कर सकेगा, यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में अनुशंसित एक कदम है। साथियों बात अगर हम 10वीं सीबीएसई के इस चेंज पैटर्न को गहराई से समझने की करें तो, नए एग्जाम पैटर्न की 3 अहम बातें, परीक्षा यानी ऑप्शनल एग्जाम में छात्रों को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की इजाजत दी जाएगी।विंटर बाउंड स्कूलों (सर्दियों में बंद रहने वाले स्कूल) के छात्रों को दोनों परीक्षाओं में से किसी में भी बैठने की इजाजत होगी। अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं हुआ है, तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि पहले और दूसरे चरण की परीक्षाओं में सेलेबस भी एक ही रहेगा और पूर्ण पाठ्यक्रम शामिल होगा, इसके साथ ही जो स्टूडेंट दोनों परीक्षा में हिस्सा लेंगे, उनके परीक्षा केंद्र एक ही होंगे,(1) अगर एग्जाम फीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही दोनों परीक्षाओं की फीस जमा करनी होगी। (2) सीबीएसई दूसरे एग्जाम के जरिए उन स्टूडेंट्स को मौका देना चाहता है, जो एक बार परीक्षा के बाद अपने परिणामों में सुधार करना चाहते हैं (3) अगर कोई स्टूडेंट साल की दोनों परीक्षाओं में हिस्सा लेता है तो उसके उन नंबरों को फाइनल माना जाएगा, जो ज्यादा होंगे, अगर किसी के पहले एग्जाम में ज्यादा नंबर आते हैं और दूसरे एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो उसके पहले चरण की परीक्षा के नंबर को फाइनल माना जा सकता है। बता दें कि स्टूडेंट्स तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की अनुमति दी जाएगी, अगर कोई स्टूडेंट पहली परीक्षा में 3 या 3 से ज्यादा विषयों में शामिल नहीं हुआ है तो उसे दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा।सीबीएसई की ओर से फरवरी में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसमें कहा गया था कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच आयोजित हो सकती है और दूसरे चरण की परीक्षाएं 5 से 20 मई के आयोजित होंगी। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2026 से वर्ष में दो बार होगी- सप्लीमेंट्री खत्म-पहली परीक्षा फरवरी में कंपलसरी, दूसरी मई में ऑप्शनल-अप्रैल जून में नतीजे,परीक्षा के नए पैटर्न में छात्रों को अंकों में बेहतर सुधार का यह मौका करियर में मील का पत्थर साबित होगा।सीबीएसई 10वीं का नया पैटर्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुरूप,परीक्षाओं में कम तनावपूर्ण माहौल व छात्रों को सीखने का बेहतर मौके देना है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कन्हा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादस्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/78882)

भाजपा ने तीन राज्यों में नियुक्त किए राज्य निर्वाचन अधिकारी, संगठनात्मक चुनावों पर निगरानी रखेंगे ये नेता

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में अपने संगठनात्मक चुनावों की निगरानी के लिए राज्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्रियों किरेन रिजिजू और हर्ष मल्होत्रा, तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को क्रमशः इन तीन राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के संगठनात्मक चुनावों के रिटर्निंग ऑफिसर के. लक्ष्मण ने एक बयान में कहा कि ये तीनों सांसद संबंधित राज्यों से पार्टी अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव में केंद्रीय पदाधिकारी की भूमिका निभाएंगे। यह नियुक्ति संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से की गई है, जो पहले से ही लंबित है और जिसका समापन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जो एक केंद्रीय मंत्री भी हैं। भाजपा के कुल 37 संगठनात्मक राज्य हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले कम से कम 19 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी आवश्यक है।

अब तक 14 राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों में अभी तक पार्टी अध्यक्षों का चुनाव नहीं हुआ है। इन राज्यों के लिए भाजपा ने जनवरी में ही राज्य निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी थी। पार्टी के संविधान के अनुसार शुरू हुई यह प्रक्रिया सितंबर पिछले वर्ष एक राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के साथ आरंभ हुई थी और इसे इस वर्ष की शुरुआत तक पूरा किया जाना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है। जे. पी. नड्डा ने जनवरी 2020 में यह पद संभाला था। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों के कारण उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और वे तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता।

इटावा कथावाचक कांड पर फिर बोले अखिलेश- आज संपूर्ण पीडीए समाज प्रत्येक पीड़ित के साथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को गैर-ब्राह्मण कथा वाचकों पर कथित हमले को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज संपूर्ण पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज प्रत्येक पीड़ित के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है।

इटावा जिले के दंदरपुर गांव में 22-23 जून की रात को दो भागवत कथा वाचकों - मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव - को कथित तौर पर ''ऊंची जाति के लोगों द्वारा मुंडन करा दिया गया और अपमानित किया गया, क्योंकि कथा वाचक यादव जाति के हैं। अखिलेश ने अपने आधिकारिक 'एक्स खाते पर एक पोस्ट में इटावा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ गिनती के प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोगों ने तो उस कलाकार को भी नहीं छोड़ा जो अपनी थाप से दुनिया देखता है। उन्होंने कहा कि उसकी ढोलक छीनकर और उस पर आरोप लगाकर ऐसे नकारात्मक लोगों ने अपने ही समाज की सहानुभूति खो दी है। जो लोग ऐसा करते हैं, वो मानवीय मानकों पर खारिज कर दिये जाने वाले 'अभारतीय और अमानवीय लोग होते हैं। उन्होंने कहा, ''आज संपूर्ण पीडीए समाज 'इटावा कथावाचक पीडीए अपमान कांड के हर पीड़ित के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है।

उन्होंने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की नई परिभाषा देते हुए इसी पोस्ट में कहा, ''पीडीए 'पीड़ा, दुख और अपमान का त्रिदंश झेलने वाले परंपरागत रूप से उपेक्षित और उत्पीड़ित लोगों के बीच आई नई चेतना एवं एकजुटता का सामूहिक, सामाजिक, सामुदायिक ऐलान है।

सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा अपने सेट किये हुए 'प्लांटेड लोगों के उपनाम का दुरुपयोग करके उप के पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर, समाज को बांटने वाली 'दुष्प्रेरित राजनीति प्रदेश में कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह सच प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है।

देश में 11 साल से अघोषित आपातकाल, कांग्रेस नेता शर्मिला ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की अध्यक्ष वाई एस शर्मिला ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 11 वर्षों से 'अघोषित आपातकाल लागू है। मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है, राष्ट्रीय संपत्ति को कॉरपोरेट घरानों के हाथों में सौंप दिया गया है और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। शर्मिला ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा, ''1975 के आपातकाल की तुलना में यह (राजग शासन) बदतर है। आज लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर (आईटी) और निर्वाचन आयोग (ईसी) सभी भाजपा के कब्जे में हैं। शर्मिला ने भाजपा और उसके सहयोगियों - तेदेपा, जनसेना पार्टी - तथा विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर पोलावरम परियोजना में कथित कटौती पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पोलावरम परियोजना, जिसे कभी जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था, उसे ''मात्र बांध बना दिया गया है और इस परियोजना के प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ के रूप में 80,000 करोड़ रुपए देने से भी कथित तौर पर इनकार कर दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी सांसद ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की 'डबल इंजन वाली सरकार राज्य पर ऋण का बोझ डालती है, लेकिन अनुदान नहीं देती। शर्मिला ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी योग की बात करते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को अनदेखा करते हैं। उन्होंने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। क्या यह

आंधी-तूफान के साथ होगी भारी बारिश, आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार से अगले पांच दिनों तक आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बिजली चमकने, तेज हवा चलने और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का अनुमान है। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, अगले पांच दिनों के दौरान उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने तथा गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 28 जून से एक जुलाई तक मौसमी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है, जिसमें तेज सतही हवाएं विशेष रूप से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा को प्रभावित करेंगी। तटीय क्षेत्रों में भी कुछ समय के लिए तेज हवाएं चल सकती हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने पाया कि उत्तरी ओडिशा और उससे सटे पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान पर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है, जो मौजूदा सामयिक परिस्थितियों में बदलाव का संकेत देता है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश और यनम में दक्षिण-पश्चिमी व पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिससे नमी का प्रवाह बढ़ने व संवहनीय गतिविधि को समर्थन मिलने की संभावना है।

सपा प्रमुख पर केशव मौर्य के गंभीर आरोप

ब्राह्मण और यादव में जातीय विद्वेष फैलाना चाहते हैं अखिलेश

कानपुर।

योगी आदित्यनाथ सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इटावा में माहौल बिगाड़ने का ठीकरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फोड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के बी. टेक. ऑडिटोरियम में भारतीय संविधान के प्रति जागरूक करने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में सम्बोधित कर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इटावा की घटना को अखिलेश यादव ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई के रूप में फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन जिस तरह से भागवत कथावाचकों को अखिलेश ने पार्टी कार्यालय बुलाकर यादवों के रूप में उनका सम्मान किया। यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इटावा की घटना में अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा है। समाज को कथावाचक प्रकरण में जातिवादी जहर से बांटने की कोशिश करना और लोगों को भड़काना सामाजिक अपराध है। सपा जो काम राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है वही उसे समाप्त वादी पार्टी बनायेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव तो मुलायम सिंह परिवार के अंतिम शासक के रूप में 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रह लिए हैं। अब उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी। अखिलेश को आपातकाल से जोड़ते हुए केशव प्रसाद मौर्य कहा कि अखिलेश यादव असली समाजवादी नहीं है असली समाजवादी वे लोग थे जिन्होंने आपातकाल के दौर में कांग्रेस से संघर्ष किया था। अखिलेश आज राहुल गांधी की गोद में बैठ गए हैं। मौर्य ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में जब युवा शक्ति सोचती है, तो देश की दिशा और दशा बदल जाती है। यह जागरूकता, और यह चेतना तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक जनआंदोलन का स्वरूप ले चुकी है, जिसमें लोकतंत्र के प्रति युवाओं की भागीदारी निर्णायक सिद्ध हो रही है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, सांसद रमेश अवस्थी, महापौर प्रमिला पाण्डेय, विधायक व पूर्व मंत्री नीलिमा कटियार, विधायक महेश त्रिवेदी, राहुल बच्चा सोनकर, भाजपा के जिलाध्यक्षगण अनिल दीक्षित, उमेश पासवान, पूर्व प्रदेश मंत्री श्री सुरेश अवस्थी और जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे।

आपातकाल पर बोले शिवराज सिंह चौहान

कांग्रेस संविधान की हत्यारी है, तानाशाही उसके डीएनए में है

नई दिल्ली।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपातकाल के दौरान अपने अनुभव को याद करते हुए कहा कि मैंने जेल में बहुत सारे अमानवीय अत्याचार देखे। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का इतना काला दौर था कि मैं अभी भी हैरान हूं कि ऐसा वास्तव में हुआ था। कोई इतना बड़ा पाप और अन्याय कैसे कर सकता है? वाराणसी में भाजपा नेता ने कहा कि उस समय मेरी उम्र 16 साल थी और मैंने 10वीं पास कर ली थी। 1974 में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था। मैं इससे जुड़ा हुआ था और चूंकि मैं अपने स्कूल का अध्यक्ष भी था, इसलिए मैं उस आंदोलन में शामिल हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मैं आपातकाल हटाओ और इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के पर्चे बांटता था। आपातकाल के आखिरी नौ महीनों में 9 अप्रैल को पुलिस को इसकी भनक लग गई। वे मेरे घर आए, मुझे थप्पड़ मारे और ऐसी गालियां दीं कि मैं दोहरा भी नहीं सकता। वे मुझे सीढ़ियों से घसीटकर नीचे लाए और पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने मेरे घुटनों और कोहनियों पर इतनी बुरी तरह मारा कि आज भी उनमें दर्द होता है। उन्होंने मुझे पूरी रात प्रताड़ित किया और फिर सुबह उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मजिस्ट्रेट के पास ले गए, जिन्होंने मुझे जेल भेजने के लिए कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। भाजपा नेता ने दावा किया कि जब मुझे हथकड़ी-बेड़ी में पैदल जेल ले जाया जा रहा था, तो रास्ते से गुजर रहे कुछ बच्चों ने मुझे देखा और कहा कि मैं जरूर चोर हूं। जब मैंने चोर शब्द सुना, तो मेरी अंतरात्मा रो पड़ी। मैंने अकेले ही नारे लगाने शुरू कर दिए कि जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा, जुल्म किया तो और लड़ूंगा... जब मैं भोपाल सेंट्रल जेल पहुंचा, तो मैं बाहर से नारे लगा रहा था और जो लोग पहले से जेल में बंद थे, वे जेल के अंदर से नारे लगा रहे थे। मैंने उस जेल में ही मन बना लिया था कि मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा। मुझे देश और समाज के लिए कुछ करना है। उन्होंने कहा कि देश आपातकाल की क्रूर कथा कभी न भूले, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान की हत्यारी है। तानाशाही उसके डीएनए में है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का अपमान करने वाली कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज जो लोग संविधान लेकर घूमते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं के पुरखों ने सत्ता में बने रहने के लिए देश में लोकतंत्र को रौंदने का काम किया था। मुझे आज भी याद है, जब मैं भोपाल सेंट्रल जेल में बंद था और हमारे साथ असगद वारसी जी भी थे। उनकी तबियत बिगड़ी, वे 3-4 दिन दर्द से कराहते रहे, उन्हें ईलाज की सुविधा नहीं मिली और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया।

गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को मिली राहत

गुजरात। शुक्रवार, 27 जून को 2013 के रेप केस में दोषी और उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उसकी अस्थायी जमानत को 7 जुलाई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की खंडपीठ ने दिया। अदालत ने यह बढ़ोतरी आसाराम के वकील की ओर से याचिका में दस्तावेज दाखिल करने के लिए मांगे गए अतिरिक्त समय के आधार पर की। हाई कोर्ट ने इससे पहले 28 मार्च 2025 को आसाराम को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। यह जमानत उसकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत 30 जून को समाप्त हो रही थी। अब जबकि 30 जून को यह अवधि खत्म हो रही थी, अदालत ने इसे 7 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

कोलकाता के लॉ कालेज में छात्रा से गैंगरेप तीन आरोपियों को 10 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कस्बा इलाके में एक लॉ छात्रा से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह हमला कथित तौर पर बुधवार को शाम को हुई। गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में दो मौजूदा छात्र हैं और तीसरा एक पूर्व छात्र है। आरोपी के वकील आजम खान ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। महिला ने आरोप लगाया है कि कॉलेज परिसर में उसके साथ कुकर्म किया गया। कोर्ट ने मंगलवार, 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत दी है। पीड़ित की शिकायत के बाद कस्बा पुलिस स्टेशन ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों में 31 साल के मोनोजीत मिश्रा (कॉलेज के पूर्व इकाई अध्यक्ष), 19 साल के जैब अहमद और 20 साल के प्रमित मुखर्जी (प्रमित मुखोपाध्याय) शामिल हैं। दो आरोपियों मोनोजीत और अहमद को 26 जून की शाम को कोलकाता में तालबगान क्रॉसिंग के पास सिद्धार्थ शंकर शिशु रॉय उद्यान के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। तीसरे आरोपी प्रमित को 27 जून को सुबह 12.30 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया गया और उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया।

बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि कोलकाता में एक कॉलेज छात्रा के साथ उसके दो वरिष्ठ छात्रों और शिक्षण संस्थान के एक पूर्व छात्र ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। एक अधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपियों को गुरुवार रात को गिरफ्तार किया गया। घटना 25 जून की शाम को हुई, जब छात्रा कॉलेज गई थी और तीनों आरोपी उसे शिक्षण संस्थान के अंदर एक कमरे में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा ने कस्बा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और तीनों आरोपियों को गुरुवार को हिरासत में लिया गया। फिलहाल मामला प्रारंभिक चरण में है। छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

भाजपा ने ममता सरकार को घेरा

भाजपा के अमित मालवीय ने इस अपराध को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा।

उन्होंने एक्स पर एक बंगाली समाचार रिपोर्ट साझा की और लिखा, भयानक! 25 जून को कोलकाता के उपनगर कस्बा में एक लॉ कॉलेज के अंदर एक महिला लॉ छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोपी कोई और नहीं, बल्कि एक पूर्व छात्र और कॉलेज के दो लोग थे।

तृणमूल का एक सदस्य इसमें शामिल- भाजपा

उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल का एक सदस्य इसमें शामिल था। हालांकि, इस दावे के लिए भाजपा नेता किसी तथ्य या साक्ष्य का हवाला नहीं दिया। उन्होंने कहा, आरजी कर का खौफ अभी भी कम नहीं हुआ है और फिर भी बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध रोजाना बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए एक दुःस्वप्न बन गया है।

महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है और बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तत्काल, समयबद्ध जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़िता को बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजे के साथ-साथ पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

चुनाव से 2 महीने पहले ऐसा क्यों?

वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर बोले तेजस्वी बोले, नीतीश और मोदी डरे हुए हैं

पटना। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के निर्देश जारी किए हैं। इसका मतलब है कि बिहार के लिए मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका मतलब है कि 8 करोड़ बिहारियों की मतदाता सूची को दरकिनार कर दिया गया है और एक नई सूची बनाई जाएगी। तेजस्वी से सवाल किया कि चुनाव से 2 महीने पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या 25 दिनों के भीतर आठ करोड़ लोगों की मतदाता सूची बनाना संभव है? मांगे गए दस्तावेज ऐसे हैं जो गरीबों के पास शायद ही हों। हमारा प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से संपर्क करेगा। सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी डरे हुए हैं। वे चाहते हैं कि गरीबों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। वे समाज के गरीब तबके से वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इससे राज्य मशीनरी का इस्तेमाल करके मतदाताओं को जानबूझकर बाहर करने का जोखिम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम को एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) से भी ज्यादा खतरनाक बताया और आरोप लगाया कि उनका राज्य, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, असली 'लक्ष्य' है। आपको बता दें कि सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा, तथा 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं को आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों और अनुसूची के अनुसार अपनी नागरिकता सिद्ध करने वाले दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

26 जून 1975 को संविधान हारी और तानाशाही जीती थी - केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

नई दिल्ली। पचास साल पहले, 25 जून 1975 को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन आया, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। यह फैसला भारत के संवैधानिक ढांचे पर एक गहरा और स्थायी दाग छोड़ गया। इसके बाद के 21 महीने ऐसे थे जिन्होंने भारतीयों की लोकतंत्र, सरकार और संविधान को देखने की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह की स्थिति इस बात की गवाह बनी कि किस प्रकार सत्ता के लालच में लोकतंत्र की जननी शर्मसार हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को 1971 के लोकसभा चुनावों में चुनावी अनियमितताओं के लिए दोषी ठहराते हुए उन्हें अयोग्य करार दिया था। इस्तीफे के दबाव में घिरकर इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को चौंकाते हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को केवल साधारण कागज पर न कि आधिकारिक लेटरहेड पर और बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल लगाने की सिफारिश कर दी। इस निर्णय को 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में सामने लाया गया। यह निर्णय हर मायने में तानाशाही की शुरुआत था। नागरिकों को दिए गए संवैधानिक अधिकार रातोंरात छीन लिए गए। अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति, आंदोलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता एक झटके में निलंबित कर दी गई। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा समाप्त हो गई और सबसे दुखद बात यह रही कि नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जाने का अधिकार भी छीन लिया गया – जिसे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आपातकाल के पहले शिकार वे विपक्षी नेता बने जो सरकार को चुनौती देने का साहस रखते थे। हजारों लोगों को काले कानून जैसे MISA (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम) और रक्षा भारत अधिनियम के तहत जेल में डाल दिया गया। लेकिन जल्द ही, हर आम नागरिक ने इस काले दौर के अत्याचारों का अनुभव किया। इस दौर में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर जबरदस्त हमला हुआ। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान अपनाए गए तानाशाही उपाय आज भी देश की सामूहिक स्मृति में एक डरावने दौर के रूप में जीवित हैं। मेरे 92 वर्षीय दादा, जो अपने रोजमर्रा के पशुपालन कार्य में लगे थे, एक दिन घायल हो गए और उन्हें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पता चला कि उस डॉक्टर पर नसबंदी लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव था, जो संजय गांधी की जनसंख्या नियंत्रण नीतियों से प्रभावित था। डॉक्टर उन्हें जबरन नसबंदी के लिए मजबूर करना चाहता था। हालात की गंभीरता को समझते हुए मेरे दादा अस्पताल से भाग निकले और अपना इलाज अधूरा छोड़ दिया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन यह घटना पूरे समुदाय पर मानसिक आघात बनकर छा गई। दुर्भाग्यवश, उनके जैसे लाखों लोगों को यह मौका नहीं मिला – 1975-77 के दौरान 1 करोड़ से अधिक लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई, जो भारत के लोकतंत्र के सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। प्रशासनिक तंत्र का जिस तरह व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग हुआ, वह बेहद शर्मनाक था। एक प्रमुख उदाहरण 24 मार्च 1976 को संजय गांधी की बीकानेर यात्रा है, जब उन्होंने युवाओं की रैली को संबोधित किया। न तो उनके पास कोई संवैधानिक पद था और न ही वह राज्य अतिथि थे। फिर भी उनकी यात्रा में सरकारी संसाधनों की भारी तैनाती हुई।

गोली का जवाब गोले से देना जानती है मौजूदा मोदी सरकार: पूर्व राजनयिक भास्वती मुखर्जी

नई दिल्ली।

पूर्व राजनयिक विवेक कटजू द्वारा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर की गई टिप्पणी एक वरिष्ठ राजनयिक के स्तर के अनुरूप नहीं है। उन्होंने पुरी द्वारा थिएटर ऑफ द अब्सर्ड शब्द का गलत अर्थ निकाला और जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश की। यह बात भारत के ही पूर्व राजनयिक भास्वती मुखर्जी ने अपने लेख में लिखी है। पुरी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की रणनीति पर कहा था कि पहले की सरकारें पाकिस्तान के झूठे बयानों को सच मानती थीं और आतंकवाद को उसकी राज्य नीति का हिस्सा होने के बावजूद बातचीत करती थीं। 26/11 के बाद भी भारत ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। आज स्थिति बदली है, अब भारत आतंक के खिलाफ सीधा और प्रभावी जवाब दे रहा है।पुरी के बयान का संदर्भ साफ था, यूपीए सरकार की आतंकवाद से निपटने की नीति को जनता और विशेषज्ञों द्वारा अक्सर कमजोर और हास्यास्पद माना गया है। कटजू का यह कहना कि मोदी सरकार की शुरुआती पाकिस्तान नीति भी उतनी ही विफल थी, भ्रामक और सतही है, क्योंकि दोनों समय के राजनीतिक संदर्भ बिल्कुल अलग थे। पुरी ने खुद स्वीकारा है कि उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से सहमति के चलते पार्टी जॉइन की। वह 1974 से 2013 तक भारतीय विदेश सेवा में रहे और अधिकतर कांग्रेस सरकारों के अंतर्गत काम किया। उस समय भारत की आतंकवाद से निपटने की रणनीति को कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपर्याप्त और कमजोर माना–खासतौर पर 26/11 के संदर्भ में। रणनीतिक संयम की नीति उस समय

कई अधिकारियों को भी स्वीकार नहीं थी। पुरी राजनेता दरअसल पूरी राजनयिक के अनुभवों से ही बने हैं, उन्होंने खुद देखा कि भारत कैसे आतंकवाद और असममित युद्ध से निपटने में असफल रहा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे उस रक्षात्मक सोच को आज भी समर्थन दें। 2005 से 2008 तक, यूपीए शासन के दौरान भारत में सात बड़े आतंकी हमले हुए–दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद और समझौता एक्सप्रेस जैसे हमलों में 2,000 से अधिक नागरिक मारे गए। 26/11 ने भारत की सुरक्षा छवि को तोड़कर रख दिया, और सरकार की प्रतिक्रिया बेहद बिखरी हुई और भ्रमित करने वाली थी। तत्कालीन कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने माना था कि पाकिस्तान पर हमला करने के बजाय संयम बरतना बेहतर होगा, लेकिन इसका कोई ठोस लाभ सामने नहीं आया। बाहरी दुनिया को भारत 'सॉफ्ट स्टेट' (कमजोर राष्ट्र) लगने लगा था। 2009 में शरम अल-शेख में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ दिए गए संयुक्त बयान में बलूचिस्तान का जिक्र करना एक बड़ी भूल थी–जिससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को गलत रूप में पेश किया गया। इन्हीं गलतियों की पृष्ठभूमि में पुरी ने मोदी सरकार की नीति का अंतर बताया, जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी, लक्षित और सीमित कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में दक्षिण एशिया को एकजुट, शांतिपूर्ण और व्यापारिक सहयोग वाला क्षेत्र बनाने के लक्ष्य से सत्ता में आए, जो यूपीए की पड़ोसी पहले नीति की निरंतरता थी। लेकिन 2016 का पठानकोट हमला इस आशावाद का अंत था। यह हमला मोदी की पाकिस्तान नीति में निर्णायक मोड़ बन गया। गौर करने की बात यह है कि यह हमला मोदी की पाकिस्तान यात्रा से पहले ही योजनाबद्ध था। इसके बाद मोदी सरकार की नीति में स्पष्ट बदलाव आया–2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट हवाई हमला, और अब पहलगाम के जवाब में आतंकवादी ठिकानों पर गहराई से हमला। इन सभी कार्रवाइयों ने भारत की रणनीति को मजबूत, संतुलित और निर्णायक बना दिया। अब भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ आतंकी संगठन युवाओं को गुमराह करने से पहले दो बार सोचते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा संकट किसी भी नेता के राजनीतिक साहस की परीक्षा होते हैं। मोदी ने ऐसे मौकों पर दृढ़ और तर्कसंगत फैसले लिए हैं, जो यूपीए सरकार की भ्रमित, कमजोर प्रतिक्रिया के ठीक विपरीत हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने 100 से ज्यादा देवी बसों को सड़कों पर उतारा, नरेला ए-9 टर्मिनल का लोकार्पण किया

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंज योजना के तहत 100 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ नरेला ए-9 टर्मिनल का लोकार्पण किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री पंकज सिंह भी मौजूद थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज हमने नरेला बस डिपो का उद्घाटन किया है और देवी इलेक्ट्रिक बसों को भी समर्पित किया है, 9 रूटों पर बसें चलेंगी।

इन्हें बेहतरीन सुविधाओं से लैस किया गया है। ये डिपो सिर्फ तीन महीने में बनकर तैयार हुआ है। हमारी कोशिश है कि दिल्ली की सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को इलेक्ट्रिक मोड पर लाया जाए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अपडेट हो और जनता को कोई परेशानी न हो। धीरे-धीरे हम व्यवस्था को पटरी पर ला रहे हैं। दिल्ली रंग-बिरंगी है, कई रंगों का इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए प्रयोग के तौर पर हरे और नारंगी रंग की बसें शुरू की गई हैं, आज से रथ यात्रा शुरू हो रही है, ये रंग भगवान जगन्नाथ को समर्पित हैं। इस दौरान पंकज सिंह ने कहा, आज बेहद खुशी और गर्व का दिन है। आज हम नरेला के 4,000 वर्ग मीटर एरिया में बने डीटीसी टर्मिनल के लोकार्पण के साथ डीटीसी देवी के बेड़े में नई बसों को जोड़ रहे हैं। नरेला बस टर्मिनल का लोकार्पण और देवी बसों की सौगात आने वाले समय में दिल्ली में परिवहन में एक नई दिशा प्रदान करेगी। डीटीसी टर्मिनल में बस ड्राइवरों और कर्मचारियों के लिए सुविधा उपलब्ध है। इसके संचालन के लिए 34 मीटर के दो नए शेड बनाए गए हैं, चार्जिंग पॉइंट्स स्टेशन, पार्किंग, कैंटीन, सुलभ शौचालय, स्वच्छ पानी है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को अनुकूल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

पीएम मोदी की नौ रैलियां, 200 सीटें होगी कवर, बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया खास प्लान

नई दिल्ली।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले, भाजपा ने अगले ढाई महीने के लिए व्यापक अभियान की योजना बनाई है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। बिहार भाजपा के एक नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक राज्य में छह रैलियों को संबोधित किया है और आने वाले दिनों में कई और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

भाजपा नेताओं ने कहा कि मोदी बिहार के नौ संभागों में से प्रत्येक में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। नियोजित नौ रैलियों में से मोदी पहले ही दो रैलियों को संबोधित कर चुके हैं - रोहतास और सारण संभाग में - जबकि शेष सात रैलियां अगले ढाई महीनों में आयोजित की जाएंगी। अंतिम तिथियों और स्थानों पर चर्चा चल रही है और एक सप्ताह के भीतर इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। यह अभियान सितंबर में राज्य चुनावों की औपचारिक घोषणा से ठीक पहले समाप्त होने वाला है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य चुनाव अभियान से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। फिलहाल, भाजपा कार्यकर्ता नए मतदाताओं की पहचान करने के लिए घर-घर जाकर दौरा कर रहे हैं और मतदाता पंजीकरण में सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी अभियान के दौरान तीन से चार बार राज्य का दौरा करने की उम्मीद है।

2029 विश्व पुलिस और फायर गेम्स की मेजबानी करेगा भारत, अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत को प्रतिष्ठित 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के लिए मेजबान देश के रूप में नामित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत गर्व का क्षण बताया। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत गर्व का क्षण है, क्योंकि भारत को प्रतिष्ठित 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के लिए मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है। शाह ने कहा कि भारत द्वारा इस आयोजन की मेजबानी

जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मित हमारे विशाल खेल बुनियादी ढांचे की वैश्विक मान्यता है। अहमदाबाद को इस आयोजन स्थल के रूप में चुना जाना, जो 50 से अधिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पुलिस, अग्निशमन और आपदा सेवाओं को एक साथ लाता है, एक खेल गंतव्य के रूप में शहर के बढ़ते कद का प्रमाण है। इससे पहले गुजरात ने गुरुवार को 2029 विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों की मेजबानी का अधिकार जीत लिया है और यह आयोजन राज्य की राजधानी अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सफल बोली पर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) का सहारा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत ने अमेरिका के बर्मिंघम में डब्ल्यूपीएफजी फेडरेशन के समक्ष एक व्यापक बोली प्रस्तुति के बाद अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में 2029 विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों (डब्ल्यूपीएफजी) की मेजबानी के लिए बोली जीत ली है।

दिल्ली को स्मार्ट और सुंदर बनाने की तैयारी में जुटी सरकार : प्रवेश वर्मा

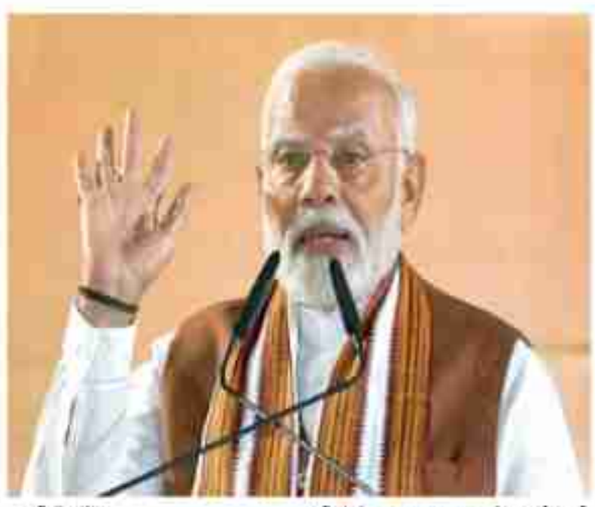

नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को स्मार्ट और सुंदर बनाना है और इसके लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है जिसमें यमुना रिवरफ्रंट का निर्माण भी शामिल है। शुक्रवार को रियल एस्टेट क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए आयोजित एक समारोह में वर्मा ने रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वालों से इन पहलों को विकसित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए।

पीडब्ल्यूडी मंत्री वर्मा ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनाईं। वर्मा ने

कहा, हमारा लक्ष्य एक स्मार्ट और सुंदर शहर बनाना है। दिल्ली सरकार यमुना रिवरफ्रंट परियोजना और अन्य परियोजनाओं पर काम कर रही है। मैं रियल एस्टेट क्षेत्र से सुझाव आमंत्रित करता हूं कि हम इस पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं।

आरोप बहुत संगीन हैं कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, पूर्व प्रेमिका का घर से निकलना हो गया था मुश्किल

नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने छेड़खानी और पीछा करने के एक मामले में कथित तौर पर दिमागी तौर पर परेशान युवक की जमानत खारिज कर दी। आरोपी की तरफ से पेश वकील ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे लेकिन युवती की शादी दूसरी जगह होने के बाद से आरोपी मानसिक रूप से परेशान हो गया। मानसिक रूप से परेशान होने की जानकारी पीड़िता को भी दी गई थी लेकिन इसके बाद भी एफआईआर दर्ज कराई। रोहिणी कोर्ट के अवकाश जज धीरेंद्र राणा की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी लगातार पीड़िता का पीछा करता रहा। युवक पर लगाए गए आरोप बहुत संगीन हैं, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। जानकारी के अनुसार, युवक पर अपनी पूर्व प्रेमिका की मां उनके परिवार को परेशान करने और धमकाने का आरोप है। इसके अलावा उनके पति के साथ भी मारपीट का आरोप है। यह मामला मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78, 79, 351(2), और 356(2) के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके क्लाइंट को झूठे मामले में फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि युवक और शिकायतकर्ता की बेटी के बीच रिश्ता था और दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन पारिवारिक कारणों से यह संभव नहीं हुआ।

इसके बाद, शिकायतकर्ता की बेटी की सगाई कनाडा में रहने वाले युवक से हो गई और वह कनाडा चली गई। जिसके कारण युवक को मानसिक और न्यूरोडेवलपमेंटल समस्याएं शुरू हुईं। वकील ने यह भी दावा किया कि युवक का इलाज मेंटल के विमहंस अस्पताल में हुआ था और उनकी मानसिक स्थिति की जानकारी शिकायतकर्ता को दी गई थी। इसके बावजूद, फरवरी 2025 में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक डॉ. राज रानी ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि युवक ने शिकायतकर्ता को लगातार परेशान किया, धमकी दी, और उनके पति के कार्यालय में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने के खिलाफ नोटिस जारी किया था, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए और कथित तौर पर फरार रहे। शिकायतकर्ता ने पुलिस को व्हाट्सएप कॉल्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूत भी सौंपे हैं।

मारुति कार और बाइक की टक्कर में दो युवक घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर।

हनुमानगंज थाना क्षेत्र के टेंगरहा मोड़ पर एक मारुतिकार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूपसे घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने तुरंत एंबुलेंस सेवुरहा सीएचसी पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार केबाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत छितौनी केअंबेडकर नगर निवासी सागर चौहान (30 वर्ष), पुत्र घूरचौहान, अपने गांव के मनीष चौहान पुत्र श्रीराम चौहान उम्र 20 वर्ष के साथ बाइक से पनियहवा की ओर जारहे थे। अभी हाइवे पर पहुंचने ही वाले थे हाइवे परपडरौना से पनियहवा की ओर

जा रही एक मारुति कारने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

पत्रकार हारुन अंसारी के पिता महातम अंसारी का निधन

तमकुही विकास खंड के ग्राम पंचायत बसंतपुरधुसकड़ के बखरा टोला निवासी एवं अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र में मोतीराम चौराहा (रामपाकड़) के संवाददाता हारून अंसारी के पिता महातम अंसारी का शुक्रवार की भोर चार बजे निधन हो गया। वे पिछले काफी समय से सांस की बीमारी से पीड़ित थे। 70 वर्षीय महातम अंसारी किसान सहकारी चीनी मिल सेवरी, खेड़ा (बोली) में कर्मचारी रहे। नौ वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे।

शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दोपहर तीन बजे उनके पार्थिव शरीर को गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन और शोक संवेदना प्रकट करने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार धनंजय मिश्र, मृत्युंजय पांडेय, मौलाना जलालुद्दीन, नसीर अली, सकलू, भुवाल, सन्तोष, धर्मवीर, दिनेश मुखी, जगदीश, राकेश लाल श्रीवास्तव, भगेसी, उमा, नरसिंह आदि ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी।

वाहन को गलती से टक्कर लगने पर ई-रिक्शा चालक को गोली मारने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक व्यक्ति को एक ई-रिक्शा चालक को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना उस समय हुई जब ई-रिक्शा चालक की गाड़ी गलती से उस व्यक्ति की कार से टकरा गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 23 जून की सुबह विनय (30) अपने ई-रिक्शा में अमित विहार से वापस अपने घर सबोली जा रहा था। उन्होंने बताया कि गगन सिनेमा के पास मोड़ते समय उसका ई-रिक्शा कथित रूप से एक काले रंग की कार से टकरा गया। अधिकारी ने बताया कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) चालक समीर शर्मा (46) ने गुस्से में आकर कथित तौर पर पिस्तौल निकाली और विनय पर गोली चला दी। उन्होंने बताया कि गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने बताया कि जीटीबी अस्पताल से पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को गोलीबारी में एक व्यक्ति के घायल होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। पुलिस ने बताया कि जीटीबी अस्पताल में ही पीड़ित का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि विनय के बयान के आधार पर नंद नगरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और धारा 3(5) (संयुक्त जवाबदेही) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद समीर को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने अपनी महिला साथी के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने उसकी महिला साथी को भी पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल पिस्तौल और काली एसयूवी जब्त कर ली गई है। अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी का उद्देश्य और आरोपी की संभावित आपराधिक पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

पोस्टमार्टम और एमएलसी प्रक्रिया होगी सुगम, एलजी ने पुलिस स्टेशन को अस्पतालों से जोड़ने की दी मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेडिको लीगल मामले (एमएलसी) को संभालने और पोस्टमार्टम जांच करने के लिए पुलिस स्टेशनों को अस्पतालों से जोड़ने व पुनर्वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह तीन नए आपराधिक न्याय अधिनियमों के तहत परिकल्पित सुधार का हिस्सा है। इस पहल के तहत दुष्कर्म, सड़क दुर्घटना और अन्य आपात स्थितियों के मामलों में शामिल पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा। साथ ही अधिक कुशल चिकित्सा और फोरेंसिक सहायता मिलेगी। इससे तत्काल चिकित्सा-कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच व्यापक समीक्षा और सहयोग होने पर एलजी ने यह मंजूरी दी। इस पहल को अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली पुलिस के बाद स्वास्थ्य विभाग के तहत एक समर्पित समिति का गठन किया गया। यह पुनर्वितरण बीएनएसएस अधिनियम, 2023 की धारा 194(3) के तहत लागू किया जा रहा है। यह पुलिस स्टेशनों को चिकित्सा-कानूनी मामलों के प्रबंधन और पोस्टमार्टम परीक्षा आयोजित करने के लिए अस्पतालों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने का काम करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधों और दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिले। चिकित्सा-कानूनी प्रक्रियाएं तुरंत और कुशलता से संचालित की जाएं।

अफवाहों पर ध्यान न दें : अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की हालत ठीक, दिल्ली जेल विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) के नेता शब्बीर अहमद शाह के स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली जेल विभाग की ओर से जवाब आया है। शाह के स्वास्थ्य के बारे में उड़ी अफवाहों का प्रशासन ने खंडन किया है। दिल्ली जेल विभाग ने गुरुवार को शब्बीर अहमद शाह के स्वास्थ्य के बारे में अफवाहों को निराधार बताया गया। दिल्ली जेल के जनसंपर्क अधिकारी अरविंद कुमार ने एक बयान में कहा कि गुलाम अहमद शाह के बेटे, कैदी शब्बीर अहमद शाह की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उसकी हालत स्थिर है। दिल्ली जेल के पीआरओ अरविंद कुमार ने कहा कि कैदी शब्बीर अहमद शाह की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस संबंध में यह कहा गया है कि उक्त कैदी को नियमित रूप से सभी चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि उसकी हालत स्थिर है। पेशाब की शिकायत के संबंध में ओपीडी परामर्श के लिए 26 जून को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली भेजा गया था। आगे के टेस्ट के लिए भर्ती किया गया है। शब्बीर की सभी रिपोर्ट सामान्य पाई गई हैं और सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है।

दिल्ली में कोरोना से 64 साल की महिला की मौत, अब तक 18 मरीज की जा चुकी जान; 347 लोग संक्रमित

नई दिल्ली। दिल्ली में घटते कोरोना के मामलों के बीच 64 वर्षीय महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला दूसरे रोग से भी पीड़ित थी। दिल्ली में अभी तक कोरोना से 18 मरीज दम तोड़ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डाटा के अनुसार, गुरुवार को 64 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हो गई। महिला को पहले से सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, गंभीर बी/एल निमोनिया, तीव्र क्रोनिक क्रोनिक किडनी डिजीज, टाइप-2 श्वसन विफलता और डीएम की शिकायत थी। इलाज के दौरान अस्पताल में कोरोना होने के बाद स्थिति गंभीर हुई और उन्होंने दम तोड़ दिया। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में अभी तक कोरोना से 18 मरीज दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 347 हो गई है। इनमें से 88 मरीज बृहस्पतिवार को मिले। दिल्ली में एक जनवरी से अभी तक कोरोना से 3398 मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें से 139 मरीज बृहस्पतिवार को ठीक हुए।

पकड़ा गया एक और बांग्लादेशी: 15 साल से दिल्ली में कर रहा था नौकरी, आधार-लाइसेंस सब बनवाया

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम जिले की वाहन चोरी निरोधक दस्ते (एएटीएस) ने पिछले 15 वर्षों से अवैध रूप से भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक ओहिद को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दिल्ली में रहते हुए उसने अपने एक बांग्लादेशी जानकार का आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख लिया था। इन दस्तावेजों की मदद से उसने अपने भारत के पहचान संबंधित दस्तावेज बनवा लिए थे। आरोपी इन्हीं दस्तावेजों की मदद से दिल्ली के अलग-अलग इलाके में नौकरी भी कर रहा था। दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस ने उसे बांग्लादेश भेजने के लिए एफआरआरओ को सौंप दिया है और उसकी निर्वासन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि एसीपी ऑपरेशन विजय कुमार के नेतृत्व में एएटीएस प्रभारी इंस्पेक्टर राम कुमार की टीम जिले में रह रहे विदेशी नागरिकों का डाटा जुटाने का काम कर रही है। इस मुहिम में पुलिस टीम को पता चला कि वसंत कुंज इलाके में अवैध बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहा है। एसआई विनोद कुमार की टीम ने आरोपी ओहिद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ओहिद ने पहले अपने को पश्चिम बंगाल का नागरिक बताया और भारत का आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी पुलिस को दिखाया। आधार कार्ड बरूचंद्र घर उत्तर पारा, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल के रहने वाले मोहम्मद रोहित शेख के नाम का था। पुलिस को आरोपी पर शक हुआ। पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की उसने बांग्लादेशी नागरिक होने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि वह 15 साल पहले एक व्यक्ति की मदद से अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत में घुसा था। आरोपी ओहिद के पास से ब्राह्मण सिरान, पोस्ट-वारी, जतावारी, ढाका, बांग्लादेश के पते पर बने उसके बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र की प्रति और बांग्लादेश के उसके पासपोर्ट की प्रति बरामद की गई।